



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 27 नवम्बर, 1996/6 अग्रहायण, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 19 अक्टूबर, 1996

संख्या कोप ए०(३)-१/८७.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग में विधि सहायक (वर्ग-III अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "अ" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग विधि सहायक (वर्ग-III अराजपत्रित) के पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 है।

(२) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियाँ.—(१) अधिसूचना संख्या कोप ए०(३)३/८५, तारीख 28-11-85 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश, सहकारिता विभाग विधि सहायक (वर्ग-III) सेवाएं भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों को एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, यात या कार्यवाही इन नियमों के अधीन विधि मान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
रवि ढींगरा,
आयुक्त एवं सचिव।

उपाबन्ध "अ"

सहायक विभाग, हिमाचल प्रदेश में विधि सहायक (अराजपन्नित) वर्ग-III के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

- | | |
|---|--|
| 1. पद का नाम | विधि सहायक। |
| 2. पदों की संख्या | 1 (एक)। |
| 3. वर्गीकरण | वर्ग-III (अराजपन्नित)। |
| 4. वेतनमान | रूपये 1800-50-2000-60-2060-70-2550-75-3000-100-3200. |
| 5. चयन पद अथवा अचयन पद | अचयन। |
| 6. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु। | 18 से 35 वर्ष : |

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में रत व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण निहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर/निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/

स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुमेष है, किन्तु इस प्रकार की स्वायत्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीबन्ध को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्पूर्व ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से प्रमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें आवेदन आमन्त्रित करने के लिए वधास्थिति पद विज्ञापित या नियोजनालयों को अभिसूचित किए जाते हैं।

(2) अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।

(क) अनिवार्य :

भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि व्यवसाय की उपाधी सहित विधि व्यवसाय में अधिवक्ता के रूप में 3 वर्षों का अनुभव या सरकारी/अर्धसरकारी संस्थानों में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय अर्हताएं :

हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।

आयु : लागू नहीं।

शैक्षणिक अर्हताएं :

जैसा कि स्तम्भ 11 में विहित किया गया है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अधिक ऐसी और अवधि के लिए बिस्तार किया जा सकेगा जैसा उक्त प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति.—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।

अतः-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जायेगा।

उपयुक्त स्तम्भ-7 में विहित अर्हता के अध्यधीन शैक्षणिक अर्हताएं पूर्ण करता हो, लिपिक वर्गीय काडर के पदधारियों (लिपिक/वरिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ सहायकों को सम्मिलित कर) में से जिनका 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके 5 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवा काल हो, प्रोन्नति द्वारा :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए सभी पात्र कर्मचारियों की एक चयन सूची तैयार की जाएगी, जिसमें उच्चतर वेतनमान वाले अभ्यर्थियों को सामूहिक रूप से अन्य पात्र व्यक्तियों से ऊपर रखा जाएगा उसके पश्चात् अगले निम्न वेतनमान वाले अभ्यर्थियों को इसी प्रकार इनके नीचे रखा जाएगा :

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-91 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिये इन शर्तों के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी :—

(1) उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर उपयुक्त निदिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों को जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम होगी :

परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तु की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तु के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड गार्मेंट कोडित परमोनेट (डिसेबल) के रूप में मान्यता दी गई है।

सर्विमिज)रुलज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे ऐक्स-मविसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्नीकल सर्विसिज)रुलज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी :

परन्तु 31-3-91 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना।

जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है।

14. सौधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षा।

किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का निम्नलिखित होना आवश्यक है:—

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) तिब्बती शरणार्थी, जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के आशय से आया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देशों या कीनिया, युगांडा, युनाईटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पहले तंजानिया और जंजीबार) ज़ाम्बिया, मालवा, जेयार और इथोपिया से, भारत में स्थायी निवास के आशय से प्रवास किया है :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

ऐसे अभ्यर्थी को, जिनके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/

साक्षात्कार में प्रविष्ट किया जा सकेगा, किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का अपेक्षित प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही दिया जाएगा।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।

सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर, और यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

16. आरक्षण

उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गये अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा

लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति

वहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेशों द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों के किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Co-op. A (3)-1/87, dated 19th October, 1996, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

CO-OPERATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 19th October, 1996

No. Co-op. A (3)-1/87.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Legal Assistant (Class-III Non-Gazetted) in the Department of Co-operation, Himachal Pradesh, as per Annexure 'A' attached to this Notification, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Co-operation Department Legal Assistant (Class-III Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1996.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal and savings.*—(1) The Himachal Pradesh Class-III Services Legal Assistant Recruitment and Promotion Rules, 1985, Notified vide Notification No. Co-op. A (3) 3/85, dated 28th November, 1985 and as amended from time to time are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules, so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,

RAVI DHINGRA,
Commissioner-cum-Secretary.

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF LEGAL ASSISTANT (NON-GAZETTED) CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF CO-OPERATION, HIMACHAL PRADESH

- | | |
|--|--|
| 1. Name of the post | Legal Assistant. |
| 2. Number of posts | 1 (One). |
| 3. Classification | Class-III (Non-Gazetted). |
| 4. Scale of pay | Rs. 1800-50-2000-60-2060-70-2550-75-3000-100-3200. |
| 5. Whether selection post or non-selection post? | Non-selection. |
| 6. Age for direct recruitment | Between 18 and 35 years : |

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis :

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government :

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not,

however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.

(a) *Essential :*

Should possess a professional degree in Law or its equivalent from any recognised University in India with 3 years experience as a practising Advocate or 5 years experience while working in a Government/semi-Government Institution.

(b) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.

Age : Not applicable.

Educational qualifications : As prescribed in Col. 11 below.

9. Period of probation, if any

Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.

100% by promotion failing which by direct recruitment.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotions/deputation/transfer is to be made

By promotion from amongst the incumbent of Clerical Cadre (including Clerks/Senior Clerks/Junior Assistants) subject to fulfilling the educational qualifications prescribed in Col. No. 7 above with 5 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* (rendered upto 31-3-1991) service;

Provided that for the purpose of promotion a select list of all eligible officials shall be prepared wherein the incumbents with higher pay scales shall be kept enbloc above the eligible persons and thereafter the incumbents next lower pay scale shall be placed below it and so on.

(1) In all cases of promotion, the *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-1991, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for the promotion subject to the conditions :—

- (i) that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-1991) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion, if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-1991, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service:

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service rendered upto 31-3-1991 shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?

As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H. P. Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.

A candidate for appointment to any service or post must be:—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva-voce* test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which, will be

determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be.

16. Reservation

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental examination

Not applicable.

18. Power to relax

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।